



आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क: O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan, रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com



रजिस्टर्ड डाक ए. डी. द्वारा

क अपील / फाइल संख्या / Appeal / File No. V2/3/RAJ/2017 मूल आदेश नं / O.I.O. No. 07/SUPDT/C.EX/AR-V/2016-17 दिनांक / Date: 25.11.2016

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

RAJ-EXCUS-000-APP-134-2017-18

आदेश का दिनांक / Date of Order: 05.12.2017 जारी करने की तारीख / Date of issue: 07.12.2017

कुमार संतोष, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित / Passed by Shri Kumar Santosh, Commissioner (Appeals), Rajkot

ग अथ आयुक्त संयुक्त आयुक्त उपायुक्त सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवाकर, राजकोट / जामनगर / गंधीधाम। द्वारा उपरोक्तित जारी मूल आदेश से उत्पन्न / Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise / Service Tax, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham

घ अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name&Address of the Appellant & Respondent :- M/s. Swastic Metal Ind., 355-A/B/C, Aji GIDC 80, Feet Road,Rajkot- 360003

इस आदेश(अपील) से उपरिक्त कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके से उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है। / Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अन्तर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अन्तर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है। / Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मुद्दामें सभी मामलों में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए। / The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताने गए अपीली के अलावा सभी अपीलीय सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहामली भवन अलावा अहमदाबाद-380016 को की जानी चाहिए। / To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above.

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमवली, 2001, के नियम 6 के अन्तर्गत निर्धारित किए गये फॉर्म EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की राशि ज्यादा की राशि और लगभग मात्रा जुड़ाना, रूप 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेकॉजिट बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। संलग्न आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। / The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac. 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

(iv) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अन्तर्गत सेवाकर नियमवली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित फॉर्म S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकती है एवं उसके साथ जिन आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न की जायेगी (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की राशि ज्यादा की राशि और लगभग मात्रा जुड़ाना, रूप 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेकॉजिट बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। संलग्न आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। / The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

(v) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अन्तर्गत सेवाकर नियमवली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित फॉर्म S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकती है एवं उसके साथ जिन आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न की जायेगी (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की राशि ज्यादा की राशि और लगभग मात्रा जुड़ाना, रूप 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्ट्रार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेकॉजिट बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। संलग्न आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। / The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.



(i) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धारा (2) एवं (2A) के अंतर्गत टैक्स की सही अवधि, सेवाकर नियमावली, 1994 के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित परप S.T.-7 में की जा सकती एवं उसके साथ अनुबन्ध, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अध्यादेश अनुबन्ध (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अध्यादेश अधीन आदेश की प्रतियाँ संलग्न की (जहाँ से एक प्रति प्रस्तुत होनी चाहिए) और अनुबन्ध द्वारा स्थापित अनुबन्ध अध्यादेश उपलब्ध, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन टैक्स करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

(ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेनॉट) के प्रति अपील के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एक के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इसे आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करने समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मात्र के 10 प्रतिशत (10%), जब मात्र एवं नुमांना विवादित है, या नुमांना, जब केवल नुमांना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाले अपेक्षित देय राशि टैक्स कांश रूप से अधिक न हो।

- (i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "जमा किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है।
- (ii) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
- (iii) सेनॉट जमा की गयी गई राशि
- (iv) सेनॉट जमा नियमावली के नियम 8 के अंतर्गत देय रकम

- बशर्ते यह कि इस धारा के प्राधान्य वित्तीय (नं. 2) अधिनियम 2014 के आरम्भ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचारणीय स्थान नहीं एवं अपील को लागू नहीं होवे।
For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall be before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores.

- Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :
- (i) amount determined under Section 11 D,
 - (ii) amount of erroneous Central Credit taken,
 - (iii) amount payable under Rule 6 of the Central Credit Rules
- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(C) भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India.
इस आदेश की पुनरीक्षण प्राधिकार निम्नलिखित मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथम परतुक के अंतर्गत अर्ध शक्ति, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन इकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन टैप भवन, ससद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाता चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B-ibid:

- (i) यदि भारत के किसी नुकसान के मामले में, जहाँ नुकसान किसी भवन को किसी कारखाने से भवन गृह के कारखाने के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भवन गृह से दूसरे भवन गृह परामर्श के दौरान, या किसी भवन गृह में या भवन में भारत के परामर्श के दौरान, किसी कारखाने या किसी भवन गृह में भारत के नुकसान के मामले में। / In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse
- (ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे भारत के निर्यात में प्रयुक्त कच्चे माल या भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (विबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India
- (iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को भारत निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.
- (iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो इन्टी केरीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्राधान्यों के तहत लागू की गई है और ऐसे आदेश जो अनुबन्ध (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (नं. 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा निर्यात की गई लॉर्डिथ अध्यादेश अध्यादेश पर या बाद में पारित किए गए हैं। / Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- (v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियाँ परप सख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संशोधन के 3 महीने के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियाँ संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साथ-साथ के लिए पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the O.O and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
- (vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए। / जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम है तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000/- का भुगतान किया जाए। / The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
- (D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का सम्बन्ध है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपरोक्त होना ही किया जाना चाहिए। इस लक्ष्य के होते हुए भी की निम्न वाली बर्तों के लिए संघट्टित अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filed to avoid scripporia work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.
- (E) महासंघट्टित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-1 के अनुसार मूल आदेश एवं संशोधन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क दिकरित जमा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs. 6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act,1975, as amended.
- (F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में उल्लिखित एवं अन्य संबंधित मामलों को सम्बन्धित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982
- (G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने के लिए, विस्तृत और नवीनतम प्राधान्यों के लिए, अपीलीय विभागीय वेबसाइट www.cbac.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbac.gov.in



3
::ORDER-IN-APPEAL ::

The present appeal has been filed by M/s. Swastic Metal Industries, 355-A/B/C, Aji GIDC, 80, Feet Road, Rajkot – 360 003 (hereinafter referred to as '**the appellant**') against the Order-In-Original No. 07/SUPDT/C.EX./AR-V/2016-17 dated 25.11.2016 (hereinafter referred to as '**the impugned order**') passed by the Superintendent, Central Excise AR-V, Rajkot (hereinafter referred to as "**the lower adjudicating authority**"):

2. Briefly stated facts of case are that appellant filed monthly return ER-1 for the month of JUNE- 2015 on 31.12.2015, delaying it by 174 Days. As per Rule 12 (1) of the Central Excise Rules 2002 & Rule 9(7) of the CENVAT Credit Rules, 2004, the production and removal of goods and other relevant particulars shall be submitted in form specified, within ten days from close of each month to the jurisdictional Range Superintendent of Central Excise. Further, as required under Central Excise Rules, 2002 (E-filing of return) CENVAT Credit Rules-2004 (4th Amendment of 2011) vide Notification No. 21 & 22/2011 both dated 14.09.2011, "Every assessee shall file electronically, the declaration or the return, as the case may be, specified in this rule". The above facts led to issuance of Notice vide F. No. C.Ex./AR-V/Swastic Metal/2015-16 dated 04.01.2016, which was adjudicated by the lower adjudicating authority vide impugned order wherein he imposed late-fee of Rs. 17,400/- for late filing of ER-1 Return for the month June-2015, under Rule 12(6) of Central Excise Rules, 2002.

3. Being aggrieved by the impugned order, the appellant preferred the present appeal mainly on the following grounds:

- (i) They had filed return of June 2015 through official web site on 04.07.2015, which indicated the message of "Successfully uploaded", however, said return did not appear on official web site, and hence again uploaded in the month of December – 2015.
- (ii) Imposing penalty ignoring the settled law that circular cannot override the provision of law.

4. In reply to the appeal memorandum, Superintendent of CGST & Excise, AR-V, Rajkot submitted details as under:

- (i) The order has been passed on the basis of Circular No. 956/17/2011-CX dated 28.09.2011 issued by CBEC, New Delhi, instructions,

procedure for electronic filling of return & payment of duty.

- (ii) The appellant did not followed instruction, return uploaded successfully on 04.07.2015 with remark to view the status after one business day, appellant not follow said remark and filed return on 31.12.2015 late by 174 days from due date. Further, appellant not complaint to department by any means and at any point of time.
- (iii) Appellant contravened Rule 12(1) of the Central Excise Rule, 2002 on account of late filling of ER-1 and therefore, late fees had been imposed rightly.

4. Personal hearing in the matter was held wherein Shri Paresh Sheth, Advocate appeared on behalf of the appellant and submitted that they had no intention not to file return and hence no penalty may be imposed on them.

FINDINGS:

5. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order, the appeal memorandum and submissions made during the personal hearing. The issue to be decided in the present appeal is whether the appellant was liable to pay late fee under Rule 12(6) of Central Excise Rule, 2002 or not.

5.1 I find that appellant had uploaded ER-1 of June, 2015 on 04.07.2015 but ignored the remarks that "Please view the status after one business day" and same was again filed by the appellant on 31.12.2015. The lower adjudicating authority has discussed Board's guidelines, instructions mentioned vide Circular No. 956/17/2011-CX dated 28.09.2011 issued by CBEC, New Delhi regarding procedure for electronic filling of returns. The facts reveal that the appellant had merely uploaded ER-1 and could not follow remarks, filed correct return on 31.12.2015 delaying it by 174 days. The appellant did not complain to the Department regarding non-filing of said return or did not make any correspondence with Range Superintendent to file manual return due to System error etc.

5.2 I find that the appellant filed proper monthly return ER-1 for the month of June 2015 on 31.12.2015 only delaying it by 174 days. It is mandatory to file a Monthly Return ER-1, electronically within 10 days from the close of the month to which the return relates and hence the appellant contravened the provisions of Rule 12(1) of the Central Excise Rules, 2002 as well Rule 9(7) of the Cenvat Credit Rules, 2004.

5.3 Sub rule (6) of Rule 12 of the Central Excise Rules, 2002 effective from 01-03-2015, reads as under:

"(6) Where any return or Annual Financial Information Statement or Annual Installed Capacity Statement referred to in this rule is submitted by the assessee after due date as specified for every return or statements, the assessee shall pay to the credit of the Central Government, an amount calculated at the rate of one hundred rupees per day subject to a maximum of twenty thousand rupees for the period of delay in submission of each such return or statement."

5.4 I find that appellant filed proper ER-1 for the month of June 2015 on 31.12.2015 delaying it by 174 days and, therefore, contravened the provisions of Rule 12(1) of the Central Excise Rules, 2002 as well Rule 9(7) of the Cenvat Credit Rules, 2004. Accordingly, appellant is liable to pay late fee @ Rs. 100/- , one hundred rupees per day subject to maximum of Rs. 20,000/- for the period of delay in accordance with provisions of Rule 12(6) *ibid*.

6. In view of above, I uphold the impugned order and reject the appeal filed by the appellant.

6.1. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

6.1 The appeal filed by the appellant stands disposed off in above terms.

(कुमार संतोष)
आयुक्त (अपील्स)

By Speed Posts

To,

M/s. Swastic Metal Industries,
355-A/B/C, Aji GIDC, 80, Feet Road,
Rajkot – 360 003

मेसेस स्वस्तिक मेटल इंडस्ट्रीज,
३५५-ABC, आजी जीआईडीसी, ८० फूट रोड,
राजकोट - ३६० ००३

Copy to:

- 1) The Chief Commissioner, Central GST & CX, Ahmedabad.
- 2) The Commissioner, Central GST & CX, Rajkot.
- 3) The Assistant Commissioner, Central GST & CX Division-I, Rajkot.
- 4) The Asst. Commissioner. (Sys.), CGST & EX, Rajkot- for uploading into website.
- 5) The Superintendent, GST & Central Excise, AR-V, Rajkot
- 6) Guard File.